

भारत सरकार
पोत परिवहन मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्ना सं. 135 जिसका उत्तर
सोमवार, 30 नवंबर, 2015/9 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है

इलाहाबाद-हल्दिया गंगा जलमार्ग परियोजना

135. श्री मोती लाल बोरा :

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि सरकार कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं को कोयले की आपूर्ति करने के लिए इलाहाबाद-हल्दिया गंगा जल मार्ग परियोजना पर काम कर रही है
- (ख) क्या सरकार को इस परियोजना के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों और पर्यावरणविदों के सुझाव प्राप्त हुए हैं
- (ग) यदि हां, तो सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है और
- (घ) सरकार का , इलाहाबाद-हल्दिया गंगा जलमार्ग परियोजना को कब तक प्रारंभ करने का लक्ष्यक है?

उत्तर

पोत परिवहन राज्यमंत्री

(श्री पोन्. राधाकृष्णलम्)

(क) : माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री ने दिनांक 10.07.2014 को दिए वर्ष 2014-15 के अपने बजट अभिभाषण में एक घोषणा की थी कि इलाहाबाद तथा हल्दिया के बीच 1620 किमी की दूरी को शामिल करते हुए गंगा नदी पर "जल मार्ग विकास" (राष्ट्रीय जलमार्ग-1) नामक एक परियोजना का विकास किया जाएगा, जो कम से कम 1500 टन के जलयानों के वाणिज्यिक नौवहन को संभव बनाएगा और यह कि यह परियोजना 4200 करोड़ रु की लागत पर छः वर्षों के समय में पूरी कर ली जाएगी। इस परियोजना का उद्देश्य एक पर्यावरण हितैशी, कम ईंधन की खपत वाले और सस्ते परिवहन का एक वैकल्पिक साधन, खासतौर पर बल्की सामान, खतरनाक सामान, कैप्टिव कार्गो तथा ओवर डायमैन्स नल कार्गो के लिए उपलब्ध करवाना है।

(ख) और (ग) : जी, हाँ। सरकार ने इस पूरी परियोजना तथा इसके प्रभावों पर और अधिक स्पष्टता हासिल करने के लिए अपेक्षित हस्तक्षेपों का आकलन करने की दृष्टि से तीन विशेषज्ञ अध्यायन प्रारंभ करवाए हैं। यह अध्ययन हैं (i) रा.ज.-1 पर विस्तृत व्यावहार्यता अध्ययन तथा इसके सहायक कार्यों के लिए विस्तृत अभियांत्रिकी; (ii) पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव आकलन (ई एस आई ए), पर्यावरणीय अल्पीकरण योजना (ई एम पी) तथा पुनर्वास कार्य योजना (आर ए पी); तथा (iii) अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र विकास रणनीति तथा बाजार विकास अध्ययन। इसके अलावा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, जो कि इस परियोजना का कार्यान्वयन अभिकरण है, ने कोलकाता, वाराणसी, पटना, दिल्ली तथा फरक्का में भागीदारों के साथ व्यापक बैठकें की हैं जिनमें पर्यावरणविदों, उद्योग, शैक्षणिकों तथा बृहत् समाज से अमूल्य प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई हैं।

(घ) : उपर्युक्त परियोजना में टर्मिनलों, जेटियों का निर्माण, नदी प्रशिक्षण तथा संरक्षण कार्य, आधुनिक स्वचालित सूचना प्रणालियाँ, नौचालनात्मक सहायक सुविधाएँ आदि शामिल हैं। परियोजनाओं का निर्माण मार्च, 2016 से प्रारंभ हो जाना प्रत्याशित है तथा प्रारंभ किए जाने वाली अंतिम परियोजनाएँ पाँच वर्षों तक का समय ले सकती हैं।
